



भा.कृ.अनु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
ICAR-ALL INDIA COORDINATED RESEARCH PROJECT ON PEARL MILLET
कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर – 342 304
Agriculture University, Mandor, Jodhpur – 342 304



Telephone : 0291-2571408 (O)

E-mail: aicpmip@gmail.com

सूचना क्रमांक –F.Tend/ARS/MND/PC/FarmStore/2022-23/21389-91 दिनांक 3.6.22

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अनु.प. - अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के फार्म एवं कार्यालय पर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बाजरा फसल में विभिन्न कृषि एवं कार्यालय कार्यों (अनुमानित लागत रु. 9,00,000/- अक्षरे नौ लाख रुपये) को करवाने के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक (स्त्री/पुरुष) उपलब्ध करवाने हेतु बन्द लिफाफे में मोहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/- जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 18.06.2022 (शनिवार) तक दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति उक्त कृषि कार्यों को अनुबन्ध पर करवाने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु धरोहर राशि 18,000/- अक्षरे अठारह हजार रुपये दिनांक 18.06.2022 (शनिवार) को दोपहर 03:00 बजे तक इस कार्यालय में केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जो कि Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। उक्त निविदा दिनांक 20.06.2022 को सुबह 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.aicpmip.res.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

Dr. Anil Kumar

परियोजना समन्वयिका



परियोजना समन्वयिका
Project coordinator
भा.कृ.अनु.प.-ऐआईसीआरपी (बाजरा)
ICAR - AICRP on Pearl Millet
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)
Agriculture University, Jodhpur (Rajasthan)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित निविदा के लिए उक्त समय पर अपना प्रतिनिधि भिजवाने की कृपा करें।
2. सूचना पट्ट, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मंडोर/बाजरा परियोजना, जोधपुर
3. निविदा समिति सदस्यगण.....

भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना,

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

खुली निविदा

एनआईटी सं. (NIT NO)	01/22-23
निविदा जमा करवाने का तरीका	ऑफलाइन
निविदा/सेवा	एक वर्ष के अनुबन्ध पर उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु।
निविदा प्राधिकृत/केता	भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
अनुमानित राशि	9 लाख
निविदा शुल्क	500/-
धरोहर राशि	अनुमानित राशि का 02 प्रतिशत (राशि रूपये 18000/-)
निविदा जारी करने की तिथि	01/06/2022
निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	18/06/2022 को दोपहर 3 बजे से
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	20/06/2022 को सुबह 11 बजे
वेबसाइट (निविदा संबंधी दस्तावेजों, शुद्धिपत्रों एवं परिशिष्टों को डाउनलोड करने हेतु)	

निविदा शुल्क (राशि 500/-) एवं धरोहर राशि रु. 18000/- केवल डिमांड ड्राफ्ट Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम से देय होगा।

भा.कृ.अनु.प. –अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) – 342 304, राजस्थान

निविदा प्रपत्र

(कार्यालय, कृषि व अन्य कार्यों के लिए अकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा सूचना क्रमांक: F.Tend/ARS/MND/PC/FarmStore/2022-23/..... दिनांक
..... अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, मण्डोर पर कृषि व अन्य
कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रपत्र के संग धरोहर राशि रुपये 18000/- (अक्षरे
अठारह हजार मात्र) रोकड/बैंक ड्राफ्ट संख्यादिनांक
देय/प्रेषित है।

निविदादाता का नाम व पूरा पता :

.....

.....दूरभाष नम्बर यदि हो : मोबाइल नम्बर ..

.....

1. निविदादाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा

क्र. सं	विवरण	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण दिनांक एवं वर्ष	संलग्नक (✓)
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
5.	आयकर (PAN number)			
6.	अनुभव प्रमाण पत्र			

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)

भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

1. इस कार्यालय हेतु अनुबन्ध पर उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों द्वारा नियम पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता है, जिसके लिए दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गई हैं एवं अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में शर्तें एवं नियम निम्न प्रकार हैं। कृपया दरें निविदा में उल्लेखित शर्तों को पढ़कर दें जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा शुल्क (राशि 500/-) एवं धरोहर राशि रू. (राशि 18000/-)केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur के नाम से देय होगा।
3. निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बिना निविदा मान्य नहीं होगी। अंतिम तिथि तक निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (Project Coordinator, ICAR-AICRP on Pearl Millet, Jodhpur) कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी।
4. निविदा के आवेदन हेतु फर्म का अपने हस्ताक्षरित मय मोहर के आवश्यक है।
5. निविदा में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
8. ठेकेदार को प्रतिदिन 08 (आठ) घंटे सेवा देने के लिए व्यक्ति लगाने होंगे एवं उन्हें जहा कहीं कार्य करने के लिए कहा जाए वहां से नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियत समय पर उपस्थित रह कर कार्य करवाना होगा। आवश्यकतानुसार अन्य कार्य करने के लिए भी ठेकेदार को कहे जाने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाने होंगे।
9. दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट एवं साफ अंकित करें।
10. श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से मासिक भुगतान अगले माह की 05 तारीख तक करवाना अनिवार्य होगा।
11. उच्चकुशल/कुशल/अकुशल श्रमिकों का भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा नियत पारिश्रमिक के अनुसार विशिष्ट/अनुभवी कार्मिकों का बिल प्रत्येक माह की तारीख तक प्रभारी, संबंधित विभाग से प्रमाणित कराकर प्रेषित करना होगा। बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौति कर भुगतान किया जायेगा।
12. भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आदेशानुसार ही श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे, अर्थात् प्रत्येक पारी में श्रमिक 8-8 घंटों प्रतिदिन के आधार पर लगाए जा सकते हैं।

13. कुशल श्रमिक योग्य एवं अनुभवी होना आवश्यक हैं।
14. अनुबंधित श्रमिक द्वारा परिसर की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबंधकर्त्ता से वसूल की जायेगी।
15. अनुबंधकर्त्ता को रूपये 500/- के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पर इकरारनामा पत्र (अनुबंध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबंध प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबंध राशि की 2.5 प्रतिशत राशि को प्रतिभूति (सुरक्षा) राशि के रूप में निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा।
16. अनुबंध के बीच में छोडने पर जमा प्रतिभूति राशि परियोजना समन्वयिका, भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबंध को शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय नुकसान /हानि की वसूली अनुबंधकर्ता से की जायेगी।
17. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर, नई निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर मूल अनुबंधकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जायेगी।
18. अनुबंध की अवधि के दौरान श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांगी की जायेगी।
19. अनुबंधकर्ता का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करावे, निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध नहीं करने की अवस्था में आनुपातिक रूप से प्रति श्रमिक प्रति दिवस की दर से अनुबंधक से वसूली की जाएगी।
20. कुशल एवं अकुशल कार्मिकों का नाम, पता एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को देना होगा जैसे ही कर्मचारी बदला जाये उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण के संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।
21. कुशल कर्मचारी को तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होगा अन्यथा कार्मिकों को अनुबंध पर नहीं रखा जायेगा।
22. अनुबंध पर रखे कार्मिकों का भुगतान भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में सुबह 11 से 2 बजे की अवधि में करना होगा एवं अगले माह के विपत्र पर इस प्रकार का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक है अन्यथा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

23. कार्य दिवस में यदि कोई कार्मिक बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो प्रति कार्मिक रूपये आनुपातिक रूप से प्रति कार्मिक प्रति दिवस विपत्र से कटौति कर दी जायेगी।
24. अनुबंधकर्ता किसी भी कर्मचारी के कार्य संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा।
25. अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान से संबंधित सूचना आवश्यक है।
26. आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौति निविदादाता को देय राशि में से भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रतिमाह की जायेगी। निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीयन/लाइसेन्स के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
27. ठेकेदार द्वारा अनुबंध आधार पर जो व्यक्ति उपलब्ध करवाता है, उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष की रहेगी।
28. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाए गए व्यक्तियों में से यदि कोई व्यक्ति लगातार 03 दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहता है तो ठेकेदार को उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा प्रतिदिन 100/- रूपयों के हिसाब से शास्ति के रूप में ठेकेदार से वसूल किये जायेंगे।
29. ठेकेदार को ठेका समाप्त होने के तीन माह पश्चात जमा धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि का भुगतान किया जायेगा यदि उसके विरुद्ध कोई बकाया नहीं हो। किसी भी प्रकार का बकाया होने की स्थिति में बकाया का समायोजन उक्त राशि में से किया जायेगा।
30. निविदादाता द्वारा इस आशय की घोषणा/अण्डरटेकिंग दी जायेगी कि वह पूर्व में किसी भी विभाग/संस्था/सरकार द्वारा असंतोषजनक कार्य/दुराचरण/दोष सिद्धि के कारण आरोपित नहीं किया गया है तथा न ही ब्लेक लिस्टेड किया गया है।
31. ड्यूटी समय पर अपने कार्य स्थल का छोड़कर अन्य कहीं नहीं जायेंगे।
32. ड्यूटी समय में अपने कार्य स्थल का अन्य कर्मचारी को कार्य संभालने तक कार्य करेंगे तथा ड्यूटी अवधि में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कार्मिक को हटा दिया जायेगा। कार्मिकों कि संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिए संबंधित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
33. अनुबंध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले कार्मिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी रहेगा।
34. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की समस्त शर्तें एवं नियम लागू होंगे।
35. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
36. न्याय क्षेत्र केवल जोधपुर ही रहेगा।

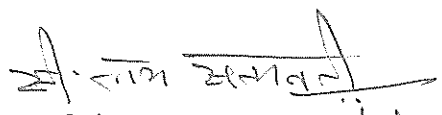
37. कार्मिकों के पी.एफ एवं ई.एस.आई. (प्रभावशील होने पर) राशि में पृथक उल्लेख निविदा में करना होगा। पी.एफ. एवं ई.एस.आई. राशि के संबंध में उल्लेख नहीं करने पर श्रम नियमों के अन्तर्गत संपूर्ण राशि जमा करवाने का दायित्व निविदाकार स्वयं का होगा। कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. निविदा के साथ निविदाकार को फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं ई. पी.एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
39. अमानत राशि रूपये 18000/- का डी.डी. संलग्न करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
40. निविदा सूचना में अंकित शर्तें निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा।
41. निविदादाता द्वारा विगत 03 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
42. फर्म द्वारा विगत 02 वकी वर्षों की कुल बिक्री (turnover) राशि न्यूनतम 10 लाख रूपये का प्रमाण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित करवाकर निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
43. निविदा प्रपत्र में अंकित निर्धारित शर्तों की पूर्ति एवं प्रपत्र में चाही गई सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर निविदा मान्य नहीं होगी।
44. कार्मिक के पी.एफ. जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा।
45. अनुबंधकर्ता द्वारा दरें एक वर्ष के अनुबंध के लिए दी जायेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकार की जाती है, उनके द्वारा उक्त दरों के अनुरूप अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि आगामी 06 माह तक बढ़ायी जा सकती है।
46. राजस्थान Transparency in Public Procurement Rule, 2013 एवं GF&AR के प्रावधान प्रभावी होंगे।
47. कार्यालय भा.कृ.अ.नु.प. अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में निविदा को भौतिक रूप से स्वीकार किया जायेगा।
48. निविदा में अंकित सेवा शुल्क की न्यूनतम दर के आधार पर निविदा अनुमोदित की जाकर संबंधित फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा।
49. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
50. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक की उक्त निविदा भाग ले सकते हैं।

है। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि बोली दरतावेज के साथ सलंगन करना आवश्यक है।

51. निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता/संवेदक द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
52. कार्मिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार कार्मिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/संवेदक का होगा। श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई राशि न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जायेगा।
53. बोलीदाता/संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
54. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, कार्मिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
55. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.सी.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
56. संवेदक द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलंगन की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

57. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
58. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये कार्मिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।
59. नियोजित कार्मिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित कार्मिकों को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
60. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
61. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
62. निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता हस्ताक्षर करेगा।
63. वित्तीय निविदा में दरें समान प्राप्त होने की दशा में कार्यादेश फर्म के गुण-अवगुण के आधार पर दिया जायेगा।

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।


 परियोजना समन्वयिका 3/6/22
 Project coordinator
 ICAR - ANUPAM (Agriculture University, Jodhpur)
 Agriculture University, Jodhpur (Rajasthan)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a) have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

~ **Signature of bidder**

Name :

Designation:

Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) **Appeal not to lie in certain cases:** No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
- (a) determination of need of procurement;
 - (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
 - (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
 - (d) cancellation of a procurement process;
 - (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate

Authority, as the case may be, shall,-

- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

1. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :
.....
.....

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-

- a) When we withdraw or modify our bid after opening of bids;
b) When we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
c) When we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
d) When we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) We are not the successful Bidder;
(ii) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) The cancellation of the procurement process; or
(v) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :

Name :

In the capacity of :

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on Day of

Corporate Seal

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

To be submitted on Rs. 50 + 30% Surcharge Non judicial stamp

Financial Bid Format (BoQ)
Turn Key Basis

क. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / चौकीदार / फलसलों की बुवाई (ले-आउट / गैप फिलिंग / पौध की रोपाई / पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य / खरपतवार निकालना, घुड़ाई करना, तुड़ाई करना, बीज निकालना, कटाई, गहाई, ओसाई व बीज पैकिंग, प्रयोगशाला व ग्रीन हाउस में कार्य / बागवानी संबंधित सहायक कार्य / विभिन्न कृषि प्रयोगों के आकडे (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद) / फसल को पक्षियों से बचाव, फार्म व कार्यालय में विभिन्न कार्य आदि। / अन्य कोई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	अकुशल श्रमिक	252 रुपये		13.00 %	3.25 %		
2	अर्द्धकुशल श्रमिक : श्रम विभाग के अधिसूचना के अनुसार अर्द्धकुशल की श्रेणी में आते हैं।	अर्द्धकुशल श्रमिक -	264 रुपये					
3	कुशल श्रमिक :- बागवान, भारी वाहनों के चालक, ट्रैक्टर चालक, टाईपिस्ट, स्टोर कीपर, पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर (अन्य कोई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	कुशल श्रमिक	276 रुपये					
4	उच्च कुशल श्रमिक :- अफाउटेट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला उपकरणों की देखरेख / रखरखाव , संकगणक ऑपरेटर, डेटा एंट्री इत्यादि (अन्य कोई भी श्रेणी जिसका कोई भी नाम हो लेकिन अकुशल कार्य करता हो)	उच्चकुशल श्रमिक -	326 रुपये					

1. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) राशि नियमानुसार प्रचलित स्लेब के अनुसार अतिरिक्त देय होगी।
2. वितीय बोली/प्राईस बिड की तालिका के स्तंभ संख्या 5, 8 व 9 की प्रविष्टि ही बोलीदाता द्वारा ऑनलाईन की जायेगी।
3. बोलीदाता द्वारा स्तंभ संख्या 5, 8 व 9 में शून्य व ऋणात्मक राशि का अंकन करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. बोलीदाता द्वारा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
5. ईपीएफ, ईएसआई व वस्तु एवं सेवाकर की राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से देय राशि के अनुसार होगी एवं राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में परिवर्तित दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता